SHRI NIRMAL CHATTERJEE: He does not answer my question. (*Interruptions*).

SHRI KALYAN ROY: You listen to us for one minute each.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: This ruling given has given rise to very important implications about the rights and privileges of the Members of the Rajya Sabha as associate Members or... (*Interruptions*).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is all right.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: It is a very important matter. It has got very far-reaching effects, and you should not shut out a discussion on this matter. It should be seriously considered by this House. (*Interruptions*).

SHRI KALYAN ROY: In the case of the Committee on the Viswa-Bharati Bill, we have co-opted Members of the Lok Sabha. Does it mean, Sir, that they are fifty per cent and we are hundred per cent... (*Interruptions*).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is a different Commttee. (*Interruptions*). Do not mix up the two, Mr. Kalyan Roy. (*Interuptions*). If you cannot appreciate it, I cannot help much.

SHRI KALYAN ROY: Does it mean, Sir, that I have less rights then...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This has been replied to. (*Interruptions*).

SHRI KALYAN ROY: Thirdly, in view of the assurance of the hon. Chairman in his Chamber that he will admit a Calling Attention, after a statement is made we will have the right to ask questions regarding the petroleum scandal and... (*Interruptions*).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is all right. Mr. Mathur.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported delay in the publication of school text books by NCERT causing harassment to school children due to shortage and high prices of text books

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR (Uttar Pradesh): Sir, I beg to call the attention of the Minister of Education and Culture and Social Welfare to the reported delay in the publication of school text books by NCERT causing harassment to school children due to shortage and high prices of text books and the remedial steps taken by the Government in this regard.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF EDUCATION AND CULTURE AND SOCIAL WELFARE (SHRIMATI SHEILA KAUL): Sir, the Honourable Members in their Calling Attention have referred to a reported delay in the publication of school text books by NCERT. Neither the Government nor NCERT is aware of any specific complaint relating to delay in publication of school text books this year.

2. I am grateful to the Members for raising this matter because it gives us an opportunity to inform all concerned about the steps taken by NCERT this year for timely publication of school text books.

3. Sir, I have information indicating an excellent position not only in respect of publication but also in respect of distribution for sale. This House will be happy to know that adequate copies for the current academic session have already been printed. I may also clarify that for distribution of its publications for sale NCERT utilises the channels established by the Publications Division of the Ministry of Information and Broadcasting. The latter have certified that supply and sale of textbooks this year have been very regular and that they have not received any complaints from any dealer, customer or institution.

4. Experience has shown that not all educational institutions are always

able to avail of the trade channels. To help such institutions, therefore, NCERT has introduced a system of inviting direct orders from educational institutions. In response to their advertisement in this connection this year, about 300 educational institutions requested for direct supply. I am happy to report, 90% or more of the requirements in each order have already been supplied.

5. The Honourable Members have also referred to textbooks being sold by NCERT at high prices. NCERT, I may point out, publishes textbooks on a 'no profit, no loss' basis. There is hardly any scope for reducing the price further. Out of 199 titles published in English and Hindi, 148 are in the price range of Re. 1 to Rs. 5, 47 are in the price range of Rs. 5 to Rs. 10 and only 4 are priced above Rs. 10. Sir, I should also point out that in some of the higher classes NCERT books are not the only ones prescribed; the Central Board of Secondary Education recommends a number of other books by other publishers along with NCERT books. A comparison of the prices of all such books will show that NCERT books are generally the cheapest.

6. Mr. Chairman, Sir, I would like to take this opportunity to assure the House that it will always be our endeavour to improve the quality of books, keep their prices to the minimum, and ensure easy availability in good time and at convenient places. The new 20 Point Programme announced by the Government, also emphasises this point.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This will continue after lunch.

सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

The House then adjourned for lunch at eight minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at three minutes past two of the clock. [Mr. Deputy Chairman in the Chair]

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैंने माननीय मंत्री जी का वक्तव्य ध्यान से पढ़ा है और उन की सद्भावनाओं के लिये हम सब आभारी हैं लेकिन फिर भी जो कमी है वह उन के वक्तव्य से दूर नहीं होगी। कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि मंत्री महोदया अवश्य कुछ करेंगी। जैसा वक्तव्य में कहा गया है एन०सी०ई०आर०टी० किताबें छापता है। इंफार्मेशन ऐंड ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री का जो एजुकेशन डिवीजन है उस के माध्यम से उन को छापा जाता है इस सवाल के तीन पहलू हैं। प्रथम कि पुस्तकें छापी कैसे जाती हैं। दूसरे वे बांटी कैसे जाती हैं और तीसरे उन का मूल्य कैसे लगाया जाता है। सर्वप्रथम मैं छपाई के बारे में आता हूं। जब एन० सी० ई० आर० टी० बना था 1961 में उस समय उस का उद्देश्य मात्र इतना था कि वह अच्छी पुस्तकों का निर्माण करे। शिक्षा मंत्रालय को सलाह दे और किस प्रकार से शिक्षा का स्तर ऊंचा किया जा सकता है इसमें सहायक हो। इसमें शक नहीं कि इस संदर्भ में एन०सी०ई०आर०टी० ने काम किया है। यदि निजी व्यक्ति इस को करता तो मैं समझता हूं कि यह जो शोधन का काम है वह नहीं हो सकता था। लेकिन गैर सरकारी कोई समिति होती जिस को सरकार का समर्थन होता वह संभवतः कर सकती थी। लेकिन इस दिशा में एन०सी०ई०आर०टी० ने काम किया है इस में संदेह नहीं। परन्तु एक परिवर्तन आया और कुछ दिनों बाद 1971 में संभवतः एन०सी०ई०आर०टी० ने किताबों का प्रकाशन शुरु किया। मुझे इस पर एतराज नहीं है कि कोई अगर सरकारी मशीनरी हो और वह किताबों का प्रकाशन शुरु करती है तो उस में, अगर कोई मुनाफा होता है तो उस को वह ले, लेकिन जहां

तक मैं समझता हूं किसी भी सरकारी विभाग का यह उद्देश्य नहीं हो सकता कि वह मुनाफा कमाया करे और जनता से पैसा इकट्ठा करे। सरकार को जनता से पैसा लेने के लिये और बहुत से माध्यम हैं। वह टैक्सेज आदि ले सकती है।

लेकिन कठिनाई यह है कि यदि एन० सी० ई० आर० टी० एक व्यापारिक संस्थान जैसा अपने आपको बना लेगा या व्यापारिक संस्थान के रूप में उसको गिरा दे तो उसमें कठिनाई हो जाती है। मंत्री महोदय ने कहा कि मैं शायद गलत कह रहा हूं लेकिन उदाहरण हैं बात चाहे पुरानी है लेकिन ऐसी कितनी ही किताबें छपी हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक आटोमोबाइल के मैगनेट हैं, उनकी पत्नी से किताब लिखाकर ले ली गई और वह कमेटी के सुपुर्द की गई। जो शिक्षाविद थे उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया और वह पड़ी रही। इसी प्रकार से एक किताब हवाई जहाज की छपी। उस पर मिस्टर लाल जो चैयरमैन थे, उनसे फोरवर्ड लिखवा लिया गया लेकिन जब देखा तो वे बहुत नाराज हो गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ ? ऐसा हुआ है। मंत्री महोदया यह पुरानी बात मैं कह रहा हूं। आज भी वह उदाहरण हो रहे होंगे, मेरी पकड़ में नहीं है। लेकिन हो सकते हैं। जब एन०सी०ई०आर०टी० केवल रिसर्च का माध्यम अपने को न बनाकर स्वयं अपना व्यापारिक दृष्टिकोण अपना ले तो कठिनाई होगी आज वह दृष्टिकोण चल रहा है आपत्ति इस बात की है।

इसके साथ ही प्रकाशन की बात आती है। श्रीमन्, सामान्यतया जितने भी सरकारी प्रकाशन हैं, सरकारी माध्यमों से आते हैं। वह सरकारी प्रेसों के द्वारा छपने चाहिए। लेकिन देखा यह जाता है कि पहले सरकारी छापेखानों के पास आर्डर भेज दिया जाता है। उसके बाद वह मना कर देते है और आहिस्ता आहिस्ता फिर निजी छापेखानों के पास आपकी किताबें जाती हैं। या तो आप इतना समय दें कि पहले ही छापेखानों से, सरकारी छापेखानों से पूछ लें और फिर प्राइवेट छापेखानों को दें। पुस्तक इसीलिए देर में छपती हैं और छपती रहेंगी, इसमें सन्देह नहीं है। विद्वानों को समय लगता है पहले उनको शुद्ध करने में, फिर जैसा सरकार का महकमा होता है उसमें कम से कम साल या छह महीने गुज़र जाना जब कि किताब का निश्चय हो और वह छपकर बाहर आ जाए और बाज़ार से पढ़ने वालों को मिल सके, उसमें साल भर बीत जाना स्वाभाविक है। तो मेरा कहना यह है कि आप कृपा करके बतायें कि कौन कौन सी पुस्तकें, कौन कौन से छापेखानों में छपी हैं और पिछले दो साल में कौन कौन सी पुस्तकें किन-किन छापाखानों में छपी हैं, उनकी छपाई का फैसला कब हुआ, किस दिन छापेखानों में गई, किस दिन बिक्री के लिए गई और किस दिन बच्चों को मिल गई और कब स्कूलों में पढ़ाई गई। ये तथ्य आप बतायेंगी तो अन्दाज हो जाएगा कि पुस्तकों की छपाई में कितना समय लगता है।

तीसरी चीज यहां पुस्तकों के बंटवारे की है। इंफार्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग मंत्रालय का पब्लिकेशन विभाग है। यहां पर मेरे पास लिस्ट है। इस विभाग ने 5–6 जगहें बनाई हुई हैं लेकिन अधिकांश उनके जो केन्द्र है वह दिल्ली के अन्दर ही हैं। सरकारी किताबें छपती हैं मद्रास में या कलकत्ता में और छपकर वह दिल्ली आती है दिल्ली आने के बाद वह

फिर कलकत्ता मद्रास या अरुणाचल प्रदेश जायेंगी। तो इसमें क्या समय नहीं लगेगा क्या गारन्टी है कि सरकारी कारखानों के अन्दर समय पर पुस्तकें छप जायेंगी या प्राइवेट में छप जायेगी ? तो इतना समय तो लगाना बड़ा स्वाभाविक है । तो यह डिले किस प्रकार से रोकी जाए, इस पर आप बतायें । उनकी ही जो पब्लिकेशन्स हैं वह मैं बताता हूं ।

आपने अपने वक्तव्य में बताया कि जितने भी सेंटर्स हैं ये सारे के सारे दिल्ली में हैं। आपने अपने वक्तव्य में यह ठीक कहा है कि बहुत सारे सरकारी आर्डर्स सीधे आ जाते हैं, उनको वह डील करते हैं । लेकिन वह तो जो सरकारी स्कूल हैं वह सीधे आर्डर दे सकते हैं परन्तु यदि कोई निजी व्यापारी आर्डर दे जिसको आपने अथाराइज किया है उसको कितना समय लगता है उसकी कठिनाई क्या है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं ।

श्रीमन्, प्राइस के बारे में आपने कहा कि किताबें महंगी नहीं हैं और मंत्री महोदया ने यह भी कहा है कि सिवाय एक को छोडकर कोई भी किताब में डिले नहीं हुई है।

जिन किताबो के मैं नाम ले रहा हूं क्या ये किताबें आज दिल्ली के बाजारों में उपलब्ध हैं कैमिस्ट्री-क्लास-अलेवंथ, फिजिक्स-क्लास इलेवंथ, बायलोजी-क्लास इलेवंथ। सोशल स्टडी-क्लास फोर्थ, सैशन प्रारम्भ हो चुका है। और प्रदेशों में तो सैशन अप्रैल से ही प्रारम्भ हो जाता है ।

श्री उपसभापति : बस हो गया ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : इस देश में जहां-जहां सेन्ट्रल स्कूल्स हैं और बाहर भी जो सेन्ट्रल स्कूल है वहां आप एन० सी० ई० आर० टी० की किताबें भेजते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि वहां भी किताबें उपलब्ध होती हैं ? प्राइसेज के बारे मे [illegible] करना चहता हूं । आपने कहा कि किताबों की कीमत एक रुपये से लेकर 10 रुपये तक [illegible] है । केवल चार किताबें 10 रुपये [illegible] की हैं । यह किताब का पोथन्ना [illegible] है । इसे देखने से ऐसा लगता है [illegible] मिनिस्टरी की रिपोर्ट है । यह [illegible] क्लास की किताब है और [illegible] इसकी कीमत है । चौथी क्लास के [illegible] का बस्ता छोटा होता है लेकिन [illegible] के लिये उसे अपने बस्ते को [illegible] पड़ता है क्योंकि उस छोटे बस्ते [illegible] यह किताब नहीं आ सकती [illegible] जिल्द भी ऐसी है कि चौथी [illegible] बच्चे से वह 15 दिन के अंदर [illegible] जायेगी । किताबें ऐसी होनी चाहिये देखने में वह अच्छी हो, और [illegible] मिनिस्टरी की रिपोर्ट जैसी किता[illegible] चौथी का बच्चा लेकर जायेगा [illegible] क्या हालत होगी, आप स्वयं [illegible] सकती हैं । इसकी कीमत भी [illegible] रुपये चार्ज कर रही हैं । [illegible] पास लिस्ट है इसमें इसकी कीमत [illegible] नहीं है क्योंकि कीमत ज्यादा [illegible] दूसरे यूनेस्को आपको कागज [illegible] ये जो अन्तर्राष्ट्रीय निकाय है [illegible] मुफ्त में कागज देते हैं । [illegible] मिलने के बाद भी यह महंगी [illegible] आप कहते हैं कि कीमतें बढ़ाई न[illegible] यह किताब मेरे पास है । इस [illegible] आरीजनल कीमत 5.45 पैसे है [illegible] मौहर लगाई गई है 6.60 पैसे [illegible] यह मुनाफा नहीं तो क्या है ?

श्री भा० दे० खोबरागडे : मुनाफा [illegible] है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर [illegible] खोरी ही है । यह जो कीमत [illegible] है यह क्या है ? (व्यवधान) [illegible] लिस्ट है । दो-तीन किताबों [illegible] कीमत मैं पढ़ देता हूं । सब की कीमत बढ़ा[illegible]

गई हैं । एक किताब की कीमत 2.35 से 3.55 कर दी गई और दूसरी किताब की कीमत 2 रुपये से 3.10 पैसे कर दी गई । मैं यह कहना चाहता हूं कि 1981-82 में जो कीमतें बढ़ाई गई हैं इनकी इंक्वायरी होनी चाहिये । (*समय की घंटी*) प्रश्न तो मैंने पूछे ही नहीं ।

श्री उपसभापति : हो गये हैं । आप को 10 मिनट हो गये हैं ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मेरे बच्चे तो हैं नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है । आपके बच्चे तो पढ़े होंगे, उनका ही ख्याल कर लीजिए ।

श्री उपसभापति : सब बच्चों ने किताबें खरीद ली होंगी ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : क्या आप एन० सी० ई० आर० टी० की वर्किंग पर, किस तरह वहां छपाई का काम होता है, बटवारे का काम होता है, इसकी एक बार दुबारा जांच करायेंगे ? क्योंकि सन् 1968-69 में कोई जांच नहीं हुई बावजूद इसके कि पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट में भी इस बारे में टिप्पणी की गई है । 1979-80 की रिपोर्ट में भी टोका है । मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि एन०सी०ई०आर०टी० की छपाई में और बंटवारे में कठिनाई अनुभव होती है, मैं यह तो नहीं कहता कि आप अपना अधिकार छोड़ दें और किसी निजी व्यापारी के हाथ में दे दें लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि क्या आप एन० सी० ई० आर० टी० को कुछ और सहुलियतें देने जा रही हैं और जो यहां पर गड़बड़ियां हैं उनकी जांच करायेंगे ताकि इतनी ज्यादा कीमतें न बढ़ें ? (*समय की घंटी*) दूसरे कमीशन की बात कहना चाहता हूं । आप उत्तर भारत को तो कमीशन देते हैं साढ़े बारह परसेंट और दक्षिण भारत को देते हैं 15 परसेंट । यह अंतर क्यों है ? आप बार-बार घंटी बजा रहे हैं इसलिये मैं बैठ जाता हूं ।

श्री उपसभापति : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्रीमती शीला कौल : मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातों के बारे में रोशनी डाली । मैं उनकी आभारी हूं । उनकी और जानकारी लेकर खुशी होगी । कुछ बातें जो इन्होंने कही हैं मुझे लगता है उनको इस बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं हैं । और अब जो जानकारी उनको मिलेगी उससे उनको इत्मीनान हो जाएगा उन्होंने पूछा कि एन० सी० ई० आर० टी० में किस तरीके से दाम लगाये जाते हैं, किताबें कसे छापी जाती हैं और कितना उसमें प्रोफिट बनता है । मैं यह कहना चाहती हूं कि यह जो प्राईसिंग है इसको पिछले साल दुबारा सोचा गया । एन० सी० ई० आर० टी० नो प्रोफिट नो लोस बेसिस पर किताबें छापता है । माननीय सदस्य ने खास तौर पर जो दाम बढ़ गये हैं उनका जिक्र किया है ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : जो किताब 5.55 रु० की थी उसके दाम 6 रु० कर दिये गये हैं ।

श्रीमती शीला कौल : आप पहले मेरी बात सुन लीजिये । सारे हिन्दुस्तान में सब को पता हैं कि कागज के दाम बढ़ गये हैं । फिर जो मैनुस्क्रिप्ट्स डेवलप करते हैं उसके रेट्स भी बढ़ गये हैं । इसके अलावा कास्ट आफ इंवेंटरी, होल्डिंग कास्ट और पैकिंग कास्ट भी बढ़ गई हैं । फ्रेट भी देना पड़ता हैं । इनके अलावा जैसा कि आपने कहा है, ट्रेड डिस्काउन्ट भी देते हैं । इस तरह से एन० सी० ई० आर० टी० में नो प्रोफिट नो लौस बेसिस पर किताबें छापी जाती हैं । जो स्टेम्प लगाने की बात आपने कही है, वह सही है ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : छपा हुआ एक मूल्य है, स्टेम्प का दूसरा मूल्य है।

श्रीमती शीला कौल : पिछली बार कुछ किताबें रह गई थीं उनके ऊपर यह स्टैम्प लगाई गई है। जो नई किताबें छापी गई उनका दाम बढ़ा हुआ है। इन दोनों को बराबर रखने के लिए यह स्टेम्प लगाई गई है। अगर यह नहीं किया जाता तो रिटेलर उसका कितना हो दाम मांग लेगा। इसको रोकने के लिए और दोनों के दाम बराबर रखने के लिए यह किया गया है।

श्री मा० दे० खोबरागड़े : अगर पुरानी किताब के दाम 5 रु० है तो उसको उसी दाम पर बेचना चाहिए था। उस पर प्रोफिट लेने का क्या मतलब होता है ?

श्रीमती शीला कौल : अगर उस पर स्टैम्प नहीं लगाई जाय तो रिटेलर को ज्यादा दाम लेने से न आप रोक सकते हैं और न मैं रोक सकती हूं। रिटेलर मनमाने दाम न मांग ले, उसको रोकने के लिये यह स्टैम्प लगाई गई हैं। इसलिए इस बारे में आपका जो भ्रम है वह सही नही है।

दूसरी बात इन्होंने यह पूछी हैं कि खाली दिल्ली में ही सेन्टर क्यों रखा गया है इसके रीजनल सेन्टर्स है। कलकत्ता में हैं, मद्रास में हैं, दिल्ली में है, बम्बई में हैं और इरादा हो रहा है कि पटना में भी सेन्टर खोला जाय, हैदराबाद में खोला जाय, लखनऊ में खोला जाय। इसलिए यह कहना कि खाली दिल्ली में ही सेन्टर है, यह बात सही नहीं है।

इन्होंने कुछ किताबों का जिक्र किया हैं और यह कहा है कि कुछ किताबें एवेलेबल नहीं है, जैसे कि फिजिक्स की किताब है। वह किताब मद्रास में छपती है। वह किताब छपकर कंटेनर ला रहा है, लेकिन फिजिक्स का कंटेनर अभी तक दिल्ली नहीं पहुंचा है। हमारा, एन० सी० ई० आर० टी० का आदमी, रोज रेलवे स्टेशन जाता है और यह पूछता है कि कंसाइनमेन्ट अभी तक दिल्ली पहुंचा या नहीं। लेकिन अभी तक वह दिल्ली नहीं पहुंचा है। इसलिए यह कहना कि इसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है सही नहीं है। इस बारे में हमको भी उतना ही [illegible] है जितना हमारे माननीय म[illegible] को है। यह जो फिजिक्स की किताब इसके बारे में इन्होंने बड़े जोरों से ज[illegible]कारी चाही है। एक किताब है 'ए[illegible]वाइरनमेन्ट' जो क्लास 4 में सोशि[illegible] स्टडीज में आती है। इसके बारे [illegible] बताया गया है कि 10 और 15 अ[illegible] तक यह किताब छप कर निकल जाए[illegible] इस तरह से जिन किताबों [illegible] इन्होंने जिक्र किया है और यह [illegible] है कि ये एवेलेबल नहीं है, ये [illegible] इन वजूहात से एवेलेबल नहीं है।

श्री वी० सत्यानारायण रेड्डी (आन्ध्र प्रदेश) : पहले ही आप इन किताबों को छापने का इंतजाम क्यों नहीं करती है ?

श्रीमती शीला कौल : वह हम [illegible] हैं और कर रहे है। अगर आप [illegible] पूछेंगे तो मैं डिटेल में बता दूंगी। मैंने उनके सवालों का जवाब दे दिया [illegible] लेकिन अगर कुछ सवाल रह गए [illegible] तो पूछ सकते हैं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : [illegible] यह पूछा था कि जब सब पुस्तकें [illegible]नल हो जाती हैं तो बाजार में [illegible] में कितना समय उनको लगता [illegible] 5 महीने लगते हैं या 6 महीने लगते हैं। दिल्ली और देश के दूसरे भाग[illegible]

में आने में उनको कितना टाइम लगता है। जून से सेशन शुरू हो जाता हैं और दिसम्बर में आर्डर आया था। अरूणाचल की अभी मैं बात कर रहा था वहां से आर्डर आया था दिसम्बर में और जून में गया, जब कि सेशन शुरू हो चुका था।

श्रीमती शीला कौल : देखिए, जो अरूणाचल की बात कर रहे हैं, मैंने बात करने के बाद जो जानकारी ली उसमें मुझे बताया गया कि जहां जो स्कूल हैं वह जुलाई में खुलते हैं। उनका जो आर्डर है, किताबें जो हैं वह पिछले 3 हफ्तों में पहुंचा दी गई हैं। (व्यवधान) . . .

श्री भा० दे० खोबरागडे : किताबों का आर्डर दिसम्बर में दिया गया है और वे जून में गई (व्यवधान) . . .

श्री उपसभापति : बताया है 3 हफ्ते पहले भेज दी गई।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैं पूछना चाहता हूं कि जब किताबें फाइनल कर लेते हैं और जब वह बाजार में आती है तो इसमें कितना समय लगता है। सवाल है एक साल डेढ़ साल, दो साल या 6 महीने कितना समय लगता है। आप पहले प्लान बनाते होंगे कि इस दिन किताब छपेगी और इस दिन वह बाजार में बच्चों को मिल जायेगी। इसका कितना पीरियड़ होता है?

श्रीमती शीला कौल : मुझे क्या पता कि कब खरीदने जाते हैं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : खरीदने के लिए कब अवेलेबल हो जाती हैं?

श्री उपसभापति : आपका क्या प्लान होता, है क्या टारगेट होता है, कितने दिनों में किताब तैयार कर लेते हैं मैनुस्क्रिप्ट छप जाने के बाद कितना समय बाजार आने में लगता है?

श्रीमती शीला कौल : जब सेशन शुरू होता है तो सेशन से पहले यह दी जाती है . . .

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : छपने में कितना समय लगता है, मार्केट में आने में कितना समय लगता है?

श्रीमती शीला कौल : प्रेस के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है तो कैसे मैं जानकारी दे सकती हूं कि कितना टाइम लगता है।

श्री भा० दे० खोबरागडे : राज्य सभा की किताब रात में छपकर सुबह मिल जाती है तो आपकी इतनी देरी क्यों लगती है? (व्यवधान) . . .

श्रीमती शीला कौल : आपने यह बात कही। राज्य सभा में कितने सदस्य हैं, 250 प्रतियां छापी जाती हैं जबकि वहां लाखों छपती हैं।

श्री उपसभापति : उनकी बात की ओर ध्यान मत दीजिए।

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE (Maharashtra): Mr. Deputy Chairman, Sir, this is very important subject relating to education in our institutions and this policy of publishing books by the NCERT has helped a lot the student community to get books at reasonable prices. The prices of these books are much lower than what the private traders used to charge. In fact, the private traders tried to sabotage the NCERT many times, because there are big profits involved and they could share the profits with publishers, stockists, book-

sellers etc. Therefore, I appreciate the efforts by the Minister to make a success of the NCERT enterprise. In fact, this is a national responsibility.

Two or three things arise out of this policy. I would like to know from the Minister what the national book policy in this regard is, whether they apportion any role to the private traders in the publication of NCERT books, whether any percentage of books is left out for publication by them, or whether NCERT is doing only one or two per cent, as they say. In the publication of books in the whole field, what is the percentage of books which are being published by the NCERT and what is left for the private traders? A statement has been made by the Minister that adequate copies for the current academic session have already been printed. I would like to know what was the requirement and how many copies have been printed. I am told the printing season is between May and October, or something like that. So I would like to know when those copies were printed and made available to the information and Broadcasting Ministry for distribution. So what is the number of copies printed and when were these printed for making available to I&B Ministry for distribution?

Another thing which is causing delay in this matter is the lack of coordination between the Education Ministry and the Information and Broadcasting Ministry. Supply and sale of text boks have been left to the Information and Broadcasting Ministry. They have to secure the orders and supply the books. Is there any coordination or liaison between the Education Ministry and the Information and Broadcasting Ministry for the purpose of distribution of books. Suppose a complaint comes to the Education Ministry about the delay in supplying orders, is there any conciliation cell or a monitoring cell between these two departments so that the books are supplied in adequate numbers and in time? As my friends has just now said about Arunachal Pradesh, the orders were placed in December and the books were not available for months together. The third point is, about 300 educational institutions requested for direct supply, I find from one statement here with me from the dealers of Kota that books were to be sent to Kota and the dealers wanted to take delivery there. When they come here they are told to take delivery here and that they were not going to be sent there and also they are asked to give an undertaking to waive their right to delivery there and take them here itself. Therefore, the question of distribution of books is a matter which requires serious consideration and there should be a reorientation in the policy. In this connection I would like to know—your statement is that —whether 90 per cent or more of the requirements in each order have already been supplied. Here it mentions only about 300 educational institutions have been given and not all. I would like to know how many educational institutions have placed orders in this matter and whether 90 per cent in respect of all educational institutions have been supplied or it is only 300 institutions as mentioned here. These are my three questions.

SHRIMATI SHEILA KAUL: The NCERT is responsible for textbooks mainly for Kendriya Vidayalayas, SBSC, Tibetan Schools and schools of public undertakings. And there are some other private schools that would like to buy these books of NCERT. These NCERT books are not committed to the requirements of the other schools. Nevertheless, these books in the market create difficulties for the regular customers because, as I said, books of NCERT are for the Kendriya Vidyalayas and the rest, as I said before.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: My question was about the percentage of books published by NCERT in the whole sector—both private and public.

SHRIMATI SHEILA KAUL: I will just tell you. Adequate copies are printed under order. Against an order

of 42.81 lakhs for classes I to VIII, we have received 4026 lakhs, which is more than what is required by these schools. The total printing order for clases IX to XII is 35.48 lakhs and we have received 28.93 lakhs. This is for 1982 to 1983 and 1983 to 1984. So, these are for the next year also.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: My question was not about how much you are printing for the Central Schools. My question was about the percentage, how much they are printing in the private sector for private schools and how much we are publishing for the public sector.

SHRIMATI SHEILA KAUL: I will tell you just now.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The NCERT publishes books for the Central Schools only, not for all schools.

SHRIMATI SHEILA KAUL: The NCERT creates prototype books and then the present orders are placed with the private agencies because their cost is lower than the Government cost. It is because the Government presses that are in Madras and Chandigarh are very big ones and for that we have to place an order of 40 lakh copies at one stretch, but we do not require all that.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: My question was about co-ordination between the Education Ministry and Information and Broadcasting Ministry.

SHRIMATI SHEILA KAUL: There is absolute co-ordination. The distribution is done in this way, that the retailer has to go and register himself and also inform how many copies he wants. But, sometimes it so happens that they go and register, but they demand more copies which are not available.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Matto, please.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): Mr. Deputy Chairman, Sir, the issue in todays discussion is about the non-availability of textbooks to the children. This is a very serious issue and should engage the attention of all the Members of the House. Suggestions have been put forward. I have seen and consulted the books that Mr. Mathur has just produced. I find from the three books that they have been printed in private presses in Naraina and some other places. I would like to tell the hon. Minister that in the first instance while these orders are placed certain conditions must be lad down. One is to ensure that at least one month before the classes start the books are available at the book stalls. This should be ensured through the contract that you enter with the printing presses. The second point that I have to make is with regard to the get-up of the books. I have seen the books displayed by Mr. J. P. Mathur The binding is extremely bad. I would request the hon. Minister that the officers of the Education Ministry should ensure that the get-up of the books is such that they do not get destroyed so soon. The third point I want to make is about the price. The hon. Minister said that NCERT is running on a no profit no loss basis. While I agree with that, when the orders are placed with the printing presses, it must be ensured that the charges are reasonable. The price of Rs. 10 for a small book of Mathematics of Class IV, to my mind, is very high, when Mr. Dhabe or Mr. Mathur said that UNESCO supplies paper free of charge. I would request the Minister that they should ensure that the get-up is all right, the price is reasonable and it should be ensured that at least one month before the onset of the session the books are made available in adequate quantities.

SHRIMATI SHEILA KAUL: Sir, I was expecting quite a different question from Mr. Matto. I thought he would ask something about the Kashmir Central Schools or other things. Anyway...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It means there is no difficulty there.

SHRIMATI SHEILA KAUL: Sure. The hon. Member has mentioned about the price. Just before it, it was

mentioned that the price of the book should not be high. Now if you want to put on more colour to the books, make them look more beautiful, as you said about the get-up, it would be costly. Just as in the case of a person in the absence of proper get-up he is bound to look shabby, similarly if you want the books to look more beautiful as is the case of the books of the public schools, the prices of the books will go up. And we have to cater to the needs of the general public.

श्री लाडली मोहन निगम (मध्य प्रदेश) : उपसभापति महोदय, मैं समझता हू कि एन सी ई आर टी का जन्म ही इसी के वास्ते हुआ था कि हिन्दुस्तान में समान शिक्षा समान किताबें सभी को एक ही कीमत पर मुहैया हो सकें। आपको शायद पता भी होगा कि राज्य सरकारें भी अपने यहां बच्चों के लिए किताबें छापती हैं। आपक सेंट्रल स्कूल राज्यों में भी चलते हैं तो मतलब मेरा कहने का यह है कि राज्यों में दो तरह की शिक्षा दी जा रही है। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि हिन्दुस्तान के हर स्कूल में समान शिक्षा हो, । क्योंकि ऊंची शिक्षा सब जगह एक समान है इसलिए प्रांतों में अगर विभिन्न शिक्षा होगी तो इससे मतभेद पैदा होगें और यही एक कारण है कि हिन्दुस्तान में आज विद्यार्थियों में इतना बड़ा असंतोष है। मेरा पहला क्वेशचन यह है कि क्या एन सी ई आर टी राज्य सरकारों के साथ सलाह लेकर उन राज्यों के पाठ्यक्रम को देखते हुए समान पुस्तकों का प्रकाशन शुरू करेगी ?

दूसरा, पाठ्यक्रम पुस्तक जितने विद्यार्थियों के लिए हैं, वे सिर्फ राज्य सरकारों के छापे खाने में अगर छपने लगें तो आपको जो किताबों को भेजने में एक जगह से दूसरी जगह, असुविधा होती है, वह नहीं होगी, इसलिए क्या आप अपनी छपाई का सरकारी [illegible] पर विकेन्द्रीकरण करेंगे कि नहीं ?

तीसरा प्रश्न यह है कि हिन्दुस्तान में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए दो कमीशन बने हैं और इस देश का यह सौभाग्य भी रहा कि इन दोनों कमीशनों के हेड इस देश के [illegible] शिक्षा शास्त्री रहे हैं। उन कमीशनों ने शिक्षा के संबंध में पुस्तकों की कैसे छपाई की जाय, उनमें क्या-क्या पाठ्यक्रम डाला जाय, इस बारे में जो सुझाव दिये है, क्या एन सी ई आर टी, जब अपनी किताबें बनाती हैं तो उनके [illegible] उन सुझावों का समावेश करती है [illegible] नहीं? और उसी के साथ चौथा [illegible] है, आपने बड़ी चालाकी से दूसरे पैराग्राफ में कहा है कि जो जरूरत [illegible] उसके मुताबिक किताबें छाप दी [illegible] आपने यह नहीं बताया कि [illegible] किसकी जरूरत है क्योंकि हिन्दुस्तान के संविधान के तहत चौदह भाषाएं [illegible] राज्यों में पढ़ाई भाषाओं में [illegible] त्रि भाषायी फार्मूला आपकी सरकार का नियम है।

तो क्या जिन राज्यों में [illegible] भाषाओं की किताबें चाहिए एन सी ई आर टी उनको कतनी-कितनी [illegible] दार की किताबें उन राज्यों [illegible] के लिए चलाई हैं ?

यह उसी के साथ चौथा प्रश्न है तो मेरे सिर्फ चार सुझाव है।

श्री उपसभापति : वह दोहराने की जरूरत नहीं है।

श्री लाडली मोहन निगम : [illegible] पांचवा सवाल —दाम वाला प्रश्न यह है कि आपने कहा कि बिना घाटे और मुनाफे के हम इसको चलाते है।

उपसभापति जी, हो यह रहा है कि इनको जबरदस्ती दाम इस वास्ते छापने पड़ते हैं--क्या यह सही नहीं है कि आप अपनी कुछ किताबें गैर-सरकारी, माने व्यक्तिगत प्रेसों में छपवाते है। आपने आर्डर दिया एक लाख चार हजार कापियां छापने का और प्रिंटर एक लाख कापियां आपकी छापता है। वह जानता है कि आपकी वितरण व्यवस्था जो है, उसमें कितनी देर लगेगी। आपके पास कोई नियंत्रण नहीं है कि वह एक लाख से डेढ़ लाख कापियां न छापे, और वह पचास हजार कापियां छाप करके बाजार में फेंक देता है। हालत यह है कि आपकी छापी हुई किताबें गोदामों में पड़ी रहती हैं और तब झक मार करके उनका दाम बढ़ जाता है, खर्चा बढ़ जाता है और आपको दाम बढ़ाने पड़ते हैं।

तो क्या जो व्यक्तिगत प्राईवेट छापेखाने में आप किताबें छपवाते हैं, उसमें क्या इस बात का नियंत्रण है, कोई आपके पास कानून है कि वह किताब वही आदमी, उसी तरीके की किताब नहीं छाप सकता और क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है इस बात का पता लगाने के लिए अगर वह किताब छप गई है--जिसको कहना चाहिए दौहरी किताब जैसे काला धन चलता है इसी तरह बाजार में शिक्षा के क्षेत्र में किताबों में भी दौहरी किताबें चल रही हैं। इसकी रोकथाम के लिए आप क्या कर रहे हैं?

श्रीमती शीला कौल : मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि एन०सी० ई० आर० टी० कोई पब्लिशिंग हाउस नहीं है। यह जो किताबें प्रोटो-टाइप बनाते हैं, न इसके उपर कोई कापीराइट है। अगर कोई प्रांत एन०सी० ई० आर०टी० की किताबें छापना चाहे, तो वहां की सरकार उन किताबों को छाप सकती हैं और हम इतनी किताबें नहीं बनाते हैं कि अगर मख्तलिफ स्टेट्स को--जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हमारे एन०सी०ई०आर०टी० में खाली कुछ स्कूल्ज के लिए, जो खास-खास मैंने बताया था जोकि पहले से उनके लिए आर्डर देते हैं, लेकिन यह जो स्टेट्स हैं, यह अपने किस्म की किताबें छापते हैं और जो लोकल वातावरण हैं, उसका बीच में डाल करके किताबों को बनाते हैं और अगर यह चाहते हैं कि एन० सी०ई०आर०टी० की जो किताबें हैं, उनमें स कोई टापिक लेना चाहें, तो उनको पूरी इजाजत हैं। इसमें एन०सी०ई०आर० टी० कोई दखल नहीं देती है।

आपने और क्या फरमाया था?

श्री लाडली मोहन निगम : मैंने कहा था कि विभिन्न भाषाओं की, उर्दू की कितनी किताबें छपी हैं, तेलुगु की कितनी छपी हैं। इस मामले में आप...(व्यवधान)

मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो प्राइमरी एजूकेशन कमीशन बना था... (व्यवधान) और आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में, उनकी जो रेकोमेंडेशन्स थी, क्या उनको आधार रख कर के एन० सी० ई० आर०टी० किताब बनाता है और जो गांधी जी का जो बेसिक ऐजुकेशन कमीशन था, उसके आधार पर बनाता है उसका समावेश है या नहीं?... (व्यवधान)

श्री गुलाम रसूल मटटो : उर्दू की किताबें नहीं मिलती हैं। माफ करियेगा, मैं भूल गया था। हमारे यहां उर्दू की किताबें नहीं मिलती हैं।

श्रीमती शीला कौल : उर्दू की किताबों के बारे में जो हमारे पास इन्फोरमेशन

है, वह यह है कि 72 टाइटल्स जो इस कैटेगरी में है छापने के लिए, उनमें से 65 टाइटल्स छप चुके हैं और बाकी जो हैं, वह छपने के प्रौसेस में हैं। मट्टो साहब ने जो फरमाया... अब तो वह सुन ही नहीं रहे हैं।

श्री उपसभापति : अब उधर बात करने लग गये।

श्रीमती शीला कौल : तो मैं बताना चाहती हूं कि 65 उर्दू की किताबें छप चुकी हैं।

श्री उपसभापति : एजूकेशन कमीशन की जो पब्लिशिंग के बारे में रेकोमेंडेशन्स थीं, वह बात कह रहे हैं।

श्री लाडली मोहन निगम : इस देश में एजूकेशन पर एक कमीशन बना, सैकंडरी एजूकेशन पर एक कमीशन बना, जिसके कि दोनों विगत राष्ट्रपति उसके अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने भी सुझाव दिया है कि हिन्दुस्तान में विद्यार्थियों के लिए प्राइमरी और सैकण्डरी एजूकेशन के लिए कैसी किताबें बननी चाहिएं और उनको एन०सी०ई०आर०टी० में जब आप किताबें तैयार करते हैं, तो उन सुझावों को उनमें अमल में ला रहे हैं कि नहीं, यह छोटा सा प्रश्न है?

श्रीमती शीला कौल : मान्यवर ऐसा है कि पिछले दिनों में एक जानकारी ऐसी मिली थी कि जो पहले की किताबें थी उनमें कुछ ऐसे टॉपिक्स डाल दिए गए थे जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए या और बातों के लिए मुनासिब नहीं था। तो इसलिए अब किताबों के ऊपर रेव्यू किया जा रहा है और रेव्यू करने पर वहां के जो एक्स्पर्टस हैं वे उसमें नए टापिक्स और नए सबजेक्ट्स डाल रहे हैं जिससे ये किताबें ज्यादा मुफीद होंगी हमारे बच्चों के इस्तेमाल के लिए ...(व्यवधान)

श्री लाडली मोहन निगम : मेरे कथन का मतलब प्रांतीय सरकारें . . .

श्री उपसभापति : वह तो उन्होंने पहले बता दिया है ...(व्यवधान) उन्होंने, कहा, राज्य सरकारें चाहें तो टाईटल छपवा सकती हैं।

श्री लाडली मोहन निगम : मेरा मतलब दूसरा है। राज्य सरकारों के अपने यहां पाठ्यक्रम अलग-अलग है और केन्द्रीय विद्यालय का भी अलग है। वे अपने-अपने पाठ्यक्रम छापते हैं। मेरा कहना है कि [illegible] सामान्य शिक्षा हो। तो क्या आपका [illegible] सी०ई०आर०टी०, या आपकी मिनिस्ट्री [illegible] जगह सामान्य स्तर की पुस्तकें उपलब्ध नहीं करा सकती है ?

श्री उपसभापति : अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहें तो उनकी किताबें छपवा सकती है...

श्री लाडली मोहन निगम : इसमें मेरा विरोध नही है लेकिन वह क्या छपवाएं। इस वास्ते मैंने कहा क्या सारे देश की एकता के लिए कुछ इस बारे में करने की सोच रहे हैं या नही? कोई कमीशन बनाएंगे कि नहीं ?

श्री उपसभापति : वह एक अलग प्रश्न है कि कोर्सेज कैसे हों। यहां मसला दुसरा उठा है। पुस्तकों के वितरण से उसका संबंध नहीं है। कोर्सेज पहले तय हों तब न किताबों के बारे में तय होगा ... (व्यवधान)...

श्रीमती शीला कौल : मान्यवर हर एक स्टेट अपनी किताबें छपवा सकती हैं और ये खास स्कूल हैं जिन के लिए एन०सी०ई०आर०टी० छपा सकता है ... (व्यवधान)...

श्री लाडली मोहन निगम : आपका नुकसान इतना हो रहा है ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : उसी के लिए तो कंट्रोल हो रहा है। डा० सिद्धू।

DR. M. M. S. SIDDHU (Uttar Pradesh): The Education Minister has said that the cost of printing at the Government press is higher than the cost of printing at the private presses. If this is correct, the no-profit-no-loss basis will be calculated at the higher cost of the Government presses and not at the cheaper cost at which books could be printed. If it is so, what steps is the Government taking to reduce the cost, since the Government presses are having higher costs as far as printing is concerned?

Secondly, there is a certain percentage of loss of paper in the printing and what is that. Because when the cost of the paper is high, then greater profit is made by just not printing the books properly and selling the paper in other channels. Thirdly, I would like to know how many times within five years a book is revised or re-printed. The practice is, where the monopoly is either with the State or with the NCERT, to go on changing the text-books every two years or every year. Therefore, it becomes a greater burden. Most of the books do not have any fundamental changes as far as science, technology or other things are concerned and no new subjects as subjects are introduced. Therefore, how many times within five years a book is re-edited, reprinted, I would like to know. I would also like to say that having a beautiful cover, either in the three colours which have been printed, which is dull or in a bright colours, does not mean any extra cost in the get-up of the book. It only shows that the cover and the diagrams have not been done in a proper colour. It would not have cost a single penny more than the actual cost of the book. Therefore, I would like to know what steps are being taken to have better, more attractive books for small children. Then it was stated that the NCERT has no copyright and anybody can print it. If you allow anybody to print, the State Government can print it and others can print it. Then what is the check to see that nobody prints more than the required number, with the result that those books will sell and the NCERT books will not sell?

Lastly I would like to know what the inventory is of the backlog of books which were not sold for any year for which the honourable Minister may have information within two years. How many books have not been sold and are still lying?

श्रीमती शीला कौल : मान्यवर, जैसा मैंने पहले कहा है, हम कोई कापीराउट एन० सी० ई० आर० टी० की किताबों का नहीं करते हैं ताकि जो स्टेट्स हैं और दूसरे लोग हैं वे इस का फायदा उठा सकें क्योंकि हम सब समझते हैं कि हमारा फर्ज है कि हम अच्छी किताबें बनाएं--प्राफिट हमें लेना नहीं है--हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकें।

कितने अरसे में हम किताब बदलते है? मैंने पहले कहा था कि हमारे वहां एक नया फार्मूला बना है। पहले जल्दी-जल्दी किताबें बदली जाती थीं, किताबों की शार्टेज हो जाती थी। एक साल में एक पढ़ी, दूसरी साल में दूसरी बदल दी। पिछले साल यह तय किया गया था—डा० सिद्धू की इनफार्मेशन के लिए—कि 5 साल तक हम किताब नहीं बदलेंगे जिससे किताबों के मिलने में आसानी हो। और आप ने क्या फरमाया था ?

डा० मदन मोहन सिंह सिद्धू : कई बातें कहीं थीं। गवर्नमेंट प्रैस में... आपने फरमाया था कि उन की कीमत

ज्यादा लेते हैं। तो कौनसा फार्मूला है जिस के ऊपर आप नो-प्राफिट नो लॉस केलकुलेट करते हैं?

श्रीमती शीला कौल : मैंने कहा था कि गवर्नमेन्ट प्रेस में बहुत कम जाते हैं, हम पब्लिक, प्राइवेट प्रेस जिस को कहते हैं उस से काम करवाते हैं। अगर हम वहां 100 भेजेंगे तो सरकारी प्रेस में 2 किताबें भेजेंगे। यह परसेंटेज हमारा जाता है, या उससे भी कम होता है। जो मैंने जिक्र किया था बड़े-बड़े प्रेस का था। जो हम को तोहफे के तरीके से बाहर से आये थे उनको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत दाम लगते हैं।

श्री उपसभापति : श्री भारद्वाज।

डा० मदन मोहन सिंह सिद्धु : मेरे सवालों का जवाब दिलवा दीजिए।

श्री उपसभापति : थोड़े में सवाल पूछिए, नहीं तो भूल जायेंगे सब।

एक माननीय सदस्य : आप मंत्री जी को कह रहे हैं या उनसे कह रहे है?

श्री उपसभापति : उन से कह रहा हूं।

डा० मदन मोहन सिंह सिद्धु : उप-सभापति जी, गेट अप के लिए नहीं कहा।

श्री उपसभापति : उस का जवाब कुछ वह दे चुकी हैं।

डा० मदन मोहन सिंह सिद्धु : आपने कहा गाजा वगैरहा लगाने में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। मैं कहता हूं उसी गाजे को.....

श्री उपसभापति : आप ने जो सजेशन दिये हैं उन को वह ध्यान में रखेंगी।

श्री राम चन्द्र भारद्वाज (बिहार) : श्रीमन् एन० सी० ई० आर० टी० की स्थापना जिस उद्देश्य को ले कर हुई थी वह उद्देश्य अब सफलता की ओर तो है, मगर छोटी-छोटी समितियों के कारण ये सवाल उठाने जा रहे हैं जो अभी सुनने को मिले। एन० सी० ई० आर० टी ने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। वियतनाम से कोलेबोरेशन किया है, जापान से पुरस्कृत हुआ है। इस तरह राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इसने कीर्तिमान स्थापित किया है शिक्षा के मामले में। इस के लिए शिक्षा विभाग, हमारे शिक्षा मंत्री और यह सभी बधाई के पात्र हैं। मगर नीचे के स्तर पर उतर कर जो उस में खामिया आ गयी है वह चिन्ता का विषय हैं। जैसा कि अभी माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा, किसी भी राज्य में, कोई भी उस पुस्तक को छाप सकता है। अगर ऐसी छूट है तो फिर तमाम जो सवाल उठाये गये है वह गलत हैं क्यों कि जब कोई छाप सकता है, कोई छाप कर बाजार में बेच सकता है और इतना बड़ा सरकारी तन्त्र उस को यदि बाजार में नहीं पहुंचा पाता है तो आप के प्रकाशक पहुंचा सकते है, जो पुस्तक विक्रेता हैं वह उन बाजारों में पहुंचा सकते है। लेकिन जो कोई कमी है, कहीं कोई बात है जिस की वजह से किताबें नहीं मिल पा रही है। कमी क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि पाठ्यक्रम की एकरूपता का जो अभाव हमारे सारे देश में हैं उस के कारण हम न इधर के रह पाते हैं, न उधर के रह पाते हैं। अतः मान्यवर मेरा निवेदन होगा कि अब शिक्षा समवर्ती सूची पर है और अभी तक किसी साफ नीति का निर्धारण नहीं हुआ है। तो क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि सारे देश के लिये पाठ्यक्रम में एक रूपता हो और यह पुस्तक छापने का काम, इनके वितरण का काम विश्व-विद्यालयों को न देकर एन०सी०ई०आर०टी० करे। अगर वह नहीं करता जैसा कि मंत्राणी जी ने कहा कि वह कोई पब्लिशिंग हाउस नहीं है तो एन०सी०ई०आर०टी० माडल पुस्तकें बाजार के लिये रिलीज कर दे और उन को वह ऐसा स्वतंत्र कर दे

[श्री रामचन्द्र भारद्वाज]

कि जो चाहे उन पुस्तकों को छापे और जो चाहे उन को बेचे। दो में से एक नीति आप को अपनानी पड़ेगी नहीं तो आये दिन हल्ला होता रहेगा और बाजार में हमारे प्रकाशक, जो गैर-सरकारी प्रकाशक हैं वे कुंजी के नाम पर या गाइड्स के नाम पर तरह-तरह की चीजें जोड़ कर इन पुस्तकों को छापेंगे और जो उद्देश्य था एन सी ई आर टी का कि कम पैसे पर सामान्य जनता को, सामान्य परिवार को पुस्तकें उपलब्ध हो सकें वह उद्देश्य पूरी तरह से फस्ट्रेट हो जायेगा। वह उद्देश्य आगे नहीं बढ़ सकेगा। मैं माननीया मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस संबंध में सोचें और संभव हो तो आश्वासन दें कि पाठ्यवस्तु की एकरूपता और कीमत की एक रूपता कायम होगी। अगर पुस्तक में गैर-सरकारी प्रकाशक कुछ बढ़ा देता है या घटा देता है तो आप क्या करेंगे। अगर किसी का कापी राइट नहीं है तो वह ऐसा कर सकता है। अतः इस काम को शिक्षा मंत्रालय अपने हाथ में रखे। मेरा निवेदन है कि बिचौलियों का काम खत्म किया जाये और यदि इंफार्मेशन और ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री द्वारा इन पुस्तकों का प्रकाशन हो, वितरण हो और एन० सी० ई० आर० टी० के द्वारा उन को लिखाया जाये तो इन दोनों के बीच में पूरा कोआर्डिनेशन हो। आज इन में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है, कोई सहयोग नही है और यही इस सारे विवाद का कारण है। इसलिये मेरा शिक्षा मंत्री जी से स्पष्ट निवेदन है कि या तो पूर्णतया एन० सी० ई० आर० टी० को एक पब्लिशिंग हाउस के रूप में स्थापित किया जाये या इसे वितरक के रूप में रखा जाये क्योंकि मुझे मालूम है कि अरविन्द मार्ग पर एक वितरण का कार्यालय भी है और लाख रुपये प्रति माह उस पर खर्च हो रहे हैं। सौ आदमी उसमें काम कर रहे हैं। तो क्या जरूरत है कि बिचौलियों को हम बीच में लायें। अगर इंफार्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री के साथ मिल कर बाजार के प्रकाशक उन पुस्तकों को बाजार में बेचते हैं और साथ में स्वयं अपनी पुस्तकें बेचते हैं और नोट्स बेचते हैं और बदनाम हम होते हैं तो उस को रोकने की कोशिश होनी चाहिए। मैं माननीया मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि और भी कुछ बातें हैं। जो विषमता पैदा करती है। उन की ओर संकेत करते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि वे ऐसी बातें करें कि यह विषमता मिटे। जैसे उत्तर और दक्षिण के बीच में विषमता यह है कि 20 प्रतिशत जहां हम दक्षिण भारत को कमीशन देते है वहां दिल्ली को 15 प्रतिशत ही देते हैं और साढे बारह प्रतिशत उत्तर के अन्य राज्यों को देते हैं। तो यह विषमता क्यों हैं यह मेरी समझ में आने लायक बात नहीं है। इस विषमता को दूर होना चाहिये।

मान्यवर दिल्ली हिन्दी भाषी राज्य है, क्षेत्र है और दिल्ली में ही हिन्दी की पुस्तकें उपलब्ध नहीं होतीं; जब दिल्ली में हिन्दी की पुस्तकें मांगी जाती हैं तो कहा जाता है कि यह हिन्दी की पुस्तकें चंड़ीगढ़ के लिये छपी हैं इसलिये यह पुस्तकें चंडीगढ़ जायेंगी। तो मेरा निवेदन है कि भाषा को किसी क्षेत्र में बांधना ठीक नहीं है। जहां के लोग जिस भाषा की पुस्तक चाहें वह उन को उपलब्ध होनी चाहिये।

अंतिम बात यह निवेदन करूंगा कि यह जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग है उस के यहां वितरण की जो प्रणाली है उस के अनुसार 1500 पुस्तक विक्रेताओं को पंजीकृत कर रखा गया है और उन को कठिनाइयां होती हैं। वह यहां आते हैं और सुपर बाजार में इंडेंट देते हैं। दूसरे दिन उन से पैसा जमा

कराया जाता है और फिर तीसरे दिन उनको पुस्तकें मिलती हैं। इस प्रकार से अगर किताबों का विक्रय होगा तो यह काम इसी तरह से आगे पीछे होता रहेगा और हम कुछ नहीं कर सकेंगे।

श्रीमती शीला कौल : मान्यवर, इससे पहले कि मैं कुछ कहूं मैं यह साफ जाहिर करना चाहती हू कि जो कापीराइट की बात मैं कर रहीं हूं, वह स्टेट के जो सरकारी स्कूल हैं, उनके लिये हैं। यह जो इम्प्रेशन है कि हर एक आदमी एन० सी० ई० आर० टी० की किताबों को छाप सकते हैं, ठीक नहीं है। लेकिन जो सरकारी स्कूल है, अगर वह चाहें तो उनको इजाजत है बगैर कापीराइट के छापने की।...

श्री उपसभापति : प्रदेश सरकारों को यह अधिकार है कि छापें, यह आपने कहा।

श्रीमती शीला कौल : जी हां, । आई० एंड बी० का जहां तक जिक्र किया गया है, उसमें कोई घपला नहीं है। जो लोग जाते हैं वह कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें कुछ रूल्स हैं। वह यें हैं कि आप जायें, वहां आर्डर दें, रजिस्टर करायें कि हमको चार हजार या तीन हजार किताबें चाहिये। लेकिन कुछ लोग वहा जाते है कहते हैं कि हमको 18 हजार किताबें चाहिए। तो जो किताबें हैं वे बराबर, ईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिये होती है, इनकी बड़ी एंमाउट नहीं मिलती जिसे वे होर्ड कर लें और बाद में उनका इस्तेमाल करें। इसलिये उनको शिकायत है कि आई० एंड बी० का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है।

SHRI SANTOSH MITRA (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, the NCERT is a national organisation which has earned a good names. But, Sir, its reputation has started diminishing recently because of the machinations of the vested interests at different levels at the level of the Government organisations, at the level of the NCERT itself and at the level of the Central Board of Secondary Education and these are there for the purpose of benefiting the private publishers. Sir, the honourable Minister now gave certain reasons for the increase in the prices of textbooks which are not tenable at all because the NCERT is getting paper free, is getting subsidized paper and no royalty is given to the writers because the expert staff is there for writing these books. Why then is this rise in prices? It is just to facilitate the sale of private publishers' books whose prices are less than the prices of the NCERT books. How is the cost manipulated? I will cite one example. The prices are increased by manipulating the input costs just by saying that NCERT has paid Rs. 18 lakhs as godown charges. One garment factory owned by the relatives of the Vigilance Officers at Badarpur was hired for Rs. 8 lakhs per year though it was not a godown for books. This is one instance and I do not want to go into all the other details. So, what I say is that there are no reasons for increasing the prices of books. But these things are going on because of certain other irregularities. An inquiry should be made into all these things. There is one thing about the books published by the private agencies in the prescribed list of the Central Board of Central Education. This practice shows that to give advantage to the private publishers this is being done. And, Sir, who has done it? In this connection, I would like to mention one thing. The Incharge of the Publication Unit, Head of the Publication Unit, was rejected thrice by the Selection Committee in 1979. But the same person has been selected by manipulation and his assistant also, the Chief Production Officer, whose selection also was rejected, has been appointed through manipulation recently. These are the two irregularities and these people I think, a section of these people, indulge in this sort of irregularities. So, I want

[Shri Satish Mitra]

to put certain questions to the honourable Education Minister. Why should the Central Board of Secondary Education prescribe private textbooks at all?

3.00 P.M.

No. 2, why the increase was exorbitant in the prices of books in the primary classes? No. 3, why can't the NCERT utilise the field units in the States for effective distribution and timely availability to the schools? Why can't the NCERT make use of Government godowns ,Another point, which may augment the income of the NCERT: Why can't the NCERT auction the paper declared unfit instead of disposing it off? Besides these, I want to make two more points. Why is there no film production for educational use being made in spite of a staff of 20 persons in the Centre for Educational Technology Film Unit? Why was Madhu Jhulka, producer, TV films, appointed for a contract of one year, sent to West Germany for a three week training, whereas permanent employees were not sent? My last point, Sir. There is some talk of NCERT Secretary seeking information about the progress report on the 20-point programme, Congress (I) manifesto. How does it come under the scope of the NCERT—seeking this information regarding the progress of these points of Congress (I) manifesto?

Sir, I demand an inquiry into the whole affairs of the NCERT. This malady is going on in the NCERT administration about the distribution of books and about the rising prices.

SHRIMATI SHEILA KAUL: For the kind information of the hon. Member, I would like to inform you that the NCERT does not get free paper. For the paper that it gets it has to pay to the Education Ministry. So, to say that it is free paper and the books should be cheap is not quite correct.

SHRI SANTOSH MITRA: Madam, are they not getting at subsidized rates?

SHRIMATI SHEILA KAUL: They have to pay a small amount. The paper they get free but the cartage has to be paid. The paper has to be brought to Delhi. And there are also godown charges to be paid.

For the information of the hon. Member, I would like to say that CBSE is an autonomous body and it has its own rules and regulations and it works according to that. Now, a mention is made about the 20-point programme. The 20-point programme is a programme of the Government, and it is not a party programme. So the Government has to ask about the progress made in this direction about education, about irrigation and other things.

SHRI SANTOSH MITRA: This is a programme of the party. This is the circular issued by the Secretary...

SHRIMATI SHEILA KAUL: It is a programme of the Government; you must know. Of course, it is Congress (I) Government. (*Interruptions*)

DR. MALCOLM S. ADISESHAIAH (Nominated): Mr. Deputy Chairman, I am somewhat in disagreement with my colleagues on both sides in regard to this question, the basic question that has been put. We are talking of the National Council of Educational Research and Training. It is not the function of the National Council to publish text books for schools. No more than it is the function of the CSIR, Council of Scientific and Industrial Research, on which the NCERT is modelled, to publish science books for the Universities. The CSIR does not publish a single textbook. Now, the NCERT is the highest educational research and training agency in the country.

As the Minister said, what they were meant to do was to publish certain prototype manuscripts in areas where the subject had to be brought up-to-date or changed or reformed

and not to supply schools with textbooks. When I was at the UNESCO and I made available 10 scientific experts who sat for 4 to 5 years in the NCERT and who helped in remodelling Physics and Chemistry text books. My question to the Minister is this. I know that the Government has set up a Committee which is now enquiring into the functioning of the NCERT. I have been asked to appear before it and I will do that. It is in order to examine the functioning of NCERT. The Minister should look into this thing so that it does not become an ordinary book publishing agency. If it is that, it will serve only some schools. This is the first danger.

The second danger is this. As we saw in the last Government regime, during the Janata Government, Government begins to interfere in the preparation of textbooks or in the modelling of textbooks. There were some questions to the effect that Marxism had entered into some geography or history textbooks. Some enquiry was also sought to be made. But it did not go very far. My question is: Will the Minister agree with me that it is not the function of the NCERT to publish textbooks and that it is the function of the NCERT to monitor the textbooks that are being published all over the country? Secondly, is it the function of the NCERT to produce prototype where some reform in the content is required. These are the two things. Further, I would like to say that as far as the State Governments are concerned and my own State is concerned, I may say that the main motivation in taking over textbooks by the State Governments was because it is one of the most profit-earning sources. Therefore, it was taken over. I must say as an educationist that there is not much of difference between what is published by the private sector after monitoring by the Boards of Selection and what is being published in the States. Therefore, I think that this question should be debated in the Council that has been set up.

SHRIMATI SHEILA KAUL: Sir, I have already mentioned that there is a task force and the hon. Member himself is there to give his views. Also, the NCERT is producing only the prototype books which can be used by others. That is exactly what he wants that they should not become publishing houses and that they should create books on prototype basis. Also, the State Governments should not become profit-earning agencies.

AN HON. MEMBER: This is not what he said.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The first point to which you replied was his question.

SHRIMATI SHEILA KAUL: Is that all right?

REFERENCE TO THE DUAL PRICE POLICY IN RESPECT OF SALE OF CEMENT

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Special Mentions.

श्री अश्विनी कुमार (बिहार) : उपसभापति महोदय, सरकार ने 27 फरवरी को सीमेंट के दामों की दोहरी नीति लागू की है। पहले सीमेंट का दाम कंट्रोल में

[उपसभाध्यक्ष (डा० रफीक जकरिया) पीठासीन हुए]

29रु० था, लेकिन कई जगहों पर यह 40रु०, 50रु० और 60रु० तक बिका था। तो इन दोनों दामों के बारे में देश के अंदर बहुत असंतोष था और देश में सीमेंट की कमी हो रही थी और सीमेंट के ऊपर ब्लैक चल रहा था और जिसके कारण बम्बई का अन्तुले कांड बहुत प्रसिद्ध हुआ, जिसमें सीमेंट की बहुत सारी चर्चा आई। सरकार ने, उस सीमेंट के ऊपर जो ब्लैक चल रहा था, उसको एक प्रकार से अपनी सहमति दे दी और नये दाम 40-43 रुपये कर दिये जिसमें सीमेंट